PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

वर्ष - 1 अंक - 1 शुक्रवार, जुलाई 3, 2026 विशाखापट्टनम हैदराबाद संपादकः गंट्याडा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

मंत्री शिवराज, मुख्यमंत्री नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया

'वीबी-जी राम जी' योजना का शुभारंभ

(पेन पावर न्यूज)
तिरुपति, २ जुलाई : आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से आज देशव्यापी '''विकसित भारत दृ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना' (टठ–ळ ट्ंउ ळ ल्वरंद)'' का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ''शिवराज सिंह चौहान'', आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ''एन. चंद्रबाबू नायडू'', उपमुख्यमंत्री ''पवन कल्याण'', केंद्रीय राज्य मंत्री ''डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी'' और ''कमलेश पासवान'', सांसद, विधायक तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ''नरेंद्र मोदी'' के नेतृत्व में देश के गरीब मजदूरों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही गांवों के विकास के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान और पारदर्शी प्रणाली की भी घोषणा की गई।

अपने संबोधन की शुरुआत '''नमः वेंकटेश्वराय'' और '''गोविंदा–गोविंदा'' के जयघोष के साथ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पवित्र भूमि से 'विकसित भारत दृ जी राम जी योजना' का शुभारंभ होना गरीबों और श्रमिकों के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद के समान है। उन्होंने प्रार्थना की कि देश का कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे, हर हाथ को काम मिले और हर पेट को भोजन मिले। इस संकल्प को ध रातल पर उतारने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई ''मनरेगा'' योजना केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की नई सोच के तहत '''विकसित भारत दृ जी राम जी योजना''' में श्रमिकों को पूरे ''125 दिनों के रोजगार की गारंटी'' दी गई है। यह केवल रोजगार के दिनों में वृद्धि नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी हाथ खाली न रहे।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि योजना के पहले ही दिन देशभर में लाखों श्रमिकों को काम मिला है और मनरेगा को एक उन्नत स्वरूप देकर 'वीबी–जी राम जी योजना' में परिवर्तित किया गया है।

योजना के वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले ही वर्ष में केंद्र सरकार का योगदान ''95,000 करोड़ रुपये से अधिक'' होगा। राज्यों की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी जोड़ने पर कुल वार्षिक व्यय लगभग ''1.51 लाख करोड़ रुपये'' तक पहुंच जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में इस योजना पर कुल ''7.5 लाख करोड़ रुपये'' खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि देश की ''2.86 लाख ग्राम पंचायतों'' तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को औसतन ''2 करोड़ रुपये से अधिक प्रति वर्ष'' प्राप्त होंगे। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत श्रमिकों के अधिकारों को कानूनी मजबूती दी गई है। यदि कोई मजदूर काम की मांग करता है तो उसे ''15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य'' होगा। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर संबंधित श्रमिक को ''बेरोजगारी भत्ता'' दिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अब किसी को भी मजदूरों के पसीने के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। मजदूरी भुगतान में देरी की पुरानी समस्या को समाप्त करने के लिए योजना में विशेष प्रावधान किया गया है। यदि मजदूरी के भुगतान में देरी होती है तो श्रमिकों को ''ब्याज सहित भुगतान'' किया जाएगा। इससे मजदूरों को उनके श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा और गरीबों की सेवा को ईश्वर की पूजा मानने वाला 'मोदी मंत्र' धरातल पर दिखाई देगा।

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय को ''6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत'' कर दिया गया है। इसके तहत ''13,000 करोड़ रुपये से अधिक'' की राशि ग्राम रोजगार सहायकों, मेट्स और अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि गांवों में श्रमिकों और विकास कार्यों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन मिलना आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना कार्य कर सकें और व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इस प्रकार यह योजना श्रमिकों के साथ–साथ ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे को भी सशक्त बनाने का कार्य करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसलाः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई

(पेन पावर न्यूज)
अमरावती, 2 जुलाईः आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (च्ैं), निगमों और सोसायटियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है और इस संबंध में सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पहले मंजूर किए गए प्रस्ताव के अनुरूप सरकार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। सरकारी आदेश के अनुसार यह निर्णय 1 जनवरी 2022 से पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू माना जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों को दोबारा सेवा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, पुनः नौकरी में शामिल होने तक की अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, इस अंतराल अवधि को वरिष्ठता (सीनियरिटी) और पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए नहीं माना जाएगा।

अदालत के निर्देशों के अनुसार, 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहे कर्मचारियों को पूर्ण सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पुनः सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं हैं, उन पर पूर्व की सेवानिवृत्ति संबंधी नियम ही लागू रहेंगे।

इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने संबंधित संस्थाओं को अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, प्रत्येक संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति को ध यान में रखते हुए निर्णय लेने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पीएसयू, निगमों और सोसायटियों को तत्काल यह आदेश भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं।

माविगन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो शून्य पर सिमट जाएंगे

जगन पर मंत्री गोट्टिपाटी की टिप्पणी

(पेन पावर न्यूज)
अमरावती, 2 जुलाईः आंध्र प्रदेश के मंत्री गोट्टिपाटी रवि कुमार ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों के मुद्दे पर चुनाव लड़कर वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीटें मिली थीं और यदि अब वे ''माविगन'' जैसे मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे, तो उनकी सीटें शून्य तक सिमट जाएंगी।

गुरुवार को टीडीपी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित शिकायत निवारण कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंत्री ने यह टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन राज्य को बर्बाद करने के इरादे से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई, जबकि अपने लिए ध्450 करोड़ खर्च करके एक महल का निर्माण कराया गया।

गोट्टिपाटी रवि कुमार ने कहा कि अमरावती के विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर जगन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण वे ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अमरावती के लिए 33,000 एकड़ भूमि की मांग स्वयं जगन ने की थी और लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने अमरावती में अपना घर बनाया है।

मंत्री ने कहा कि जनता ने इसी कारण वाईएसआरसीपी को सबक सिखाया और पार्टी को केवल 11 सीटों तक सीमित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए दिन–रात मेहनत कर रहे हैं।

मेरे साथ चलने वालों को मैं कभी नहीं भूलूंगा : मंत्री लोकेश

(पेन पावर न्यूज)
अमरावती, 2 जुलाई : आंध्र प्रदेश के शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि वे अपनी युवा गलम पदयात्रा के दौरान उनके साथ चलने वाले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलेंगे।

गुरुवार को लोकेश ने तिरुपति में कम्मा कल्याण एवं विकास निगम के अध्यक्ष नादेन्डला ब्रह्मम चौधरी के विवाह समारोह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने युवा गलम टीम के सदस्यों से आत्मीयता से मुलाकात की और पदयात्रा के दिनों की यादें ताजा कीं।

लोकेश ने लगभग 15 मिनट तक कार्यकर्ताओं से बातचीत की और युवा गलम की सफलता में टीडीपी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में कथित दमन और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करते हुए पदयात्रा को सफल बनाने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि ''कार्यकर्ता ही नेता है'' के सिद्धांत के साथ टीडीपी अपने कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

लोकेश ने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 20 लाख रोजगार सृजित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत जॉब कैलेंडर जारी करना, शिक्षकों के पदों को भरना तथा कांस्टेबल भर्ती जैसे कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस अवसर पर उन्होंने दोहराया कि युवा गलम पदयात्रा के माध्यम से बना संबंध स्थायी है और कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा।

दूसरों को खुशहाल देखना जगन को बर्दाश्त नहीं होता : मंत्री कोल्लू रविंद्र

(पेन पावर न्यूज)
कृष्णा जिला : आंध्र प्रदेश के मंत्री कोल्लू रविंद्र ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं जगन राज्य के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि चंद्रबाबू राज्य के विकास और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जगन राजनीतिक उद्देश्य से बयानबाजी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बुधवार को जगन द्वारा की गई टिप्पणियां उनके सोचने के तरीके का उदाहरण हैं। रविंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि कभी जगन अमरावती को राजधानी बताते हैं, तो कभी कहते हैं कि ''नहीं, हमारा स्टैंड माविगन है।''

कोल्लू रविंद्र ने लोगों से अपील की कि वे वाईएसआरसीपी प्रमुख की बदलती हुई राजनीतिक स्थितियों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पहले उनकी पार्टी अमरावती के समर्थन की बात करती थी, लेकिन चुनावों से पहले और बाद में तीन राजधानियों के मुद्दे पर राजनीति करती रही। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को जनता ने केवल 11 सीटों तक सीमित कर दिया।

मंत्री ने आलोचना करते हुए कहा कि अब जगन ''माविगन'' की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति नहीं देख सकता, वही इस तरह का व्यवहार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जगन कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

रविंद्र ने आरोप लगाया कि हाल ही में जगन ने अपने समर्थकों को सीआरडीए संरक्षण समिति के नाम पर राजधानी क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भेजा था। उन्होंने दावा किया कि वहां के किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें वापस भेज दिया।

मंत्री ने सवाल किया कि क्या जगन इसी तरह के राजनीतिक नाटक जारी रखकर क्षेत्रों के बीच विवाद पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन लोगों, जातियों और धर्मों के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। राज्य के लोगों से स्थिति पर ध्यान देने की अपील करते हुए रविंद्र ने कहा कि जगन पहले तीन राजधानियों के मुद्दे पर चुनाव लड़कर केवल 11 सीटों तक सीमित रह गए थे। उन्होंने टिप्पणी की कि यदि वे ''माविगन'' के मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे, तो जनता उन्हें शून्य सीटों तक सीमित कर देगी।

संपादकीय

त्रिशंकु' में फंसे त्रिभाषा के विद्यार्थी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रस्ताव का छात्रों के अभिभावकों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक ओर नीति यह स्वीकार करती है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक ज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर त्रिभाषा सूत्र के तहत दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य बनाती है। यही विरोधाभास विवाद का मुख्य कारण है। एक ही नीति में अंग्रेजी को वैश्विक भाषा के रूप में स्वीकार करना और साथ ही दो भारतीय भाषाएँ सीखने की अनिवार्यता लागू करना परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रतीत होते हैं। अनेक अभिभावकों और शिक्षाविदों का मानना है कि इन दोनों नीतियों को एक साथ लागू करने से छात्रों का भविष्य 'त्रिशंकु' की स्थिति में फंस सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में यदि कोई छात्र अंग्रेजी के साथ फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो उसे वह अवसर मिलता है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत उसे एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य होगा, भले ही वह उसके लिए पूरी तरह नई क्यों न हो। इससे विद्यार्थियों पर शैक्षणिक बोझ बढ़ने की आशंका है।

कई छात्र कंप्यूटर कोडिंग, गणित, विज्ञान या अन्य आधुनिक विषयों में अधिक समय देना चाहते हैं। लेकिन त्रिभाषा व्यवस्था के कारण उन्हें हिंदी, संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना पड़ सकता है। कुछ अभिभावकों का तर्क है कि अतिरिक्त भाषा सीखने में लगने वाला समय और ऊर्जा गणित, विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के अध्ययन में लगाई जाए तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाना है और कक्षा 7, 8 तथा 9 में भी छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी, जिनमें दो भारतीय भाषाएँ शामिल होंगी। ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र अंग्रेजी के साथ फ्रेंच पढ़ रहा है, तो उसे फ्रेंच छोड़कर किसी भारतीय भाषा का चयन करना पड़ सकता है। यह स्थिति विद्यार्थियों की दसवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी और प्रदर्शन पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसी पृष्ठभूमि में अभिभावकों और छात्र संगठनों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया निर्णय लिया है। इसके अनुसार कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थी अपनी पहले से पढ़ी जा रही विदेशी भाषाएँ, जैसे फ्रेंच या जर्मन, जारी रख सकेंगे। उन्हें केवल एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़नी होगी। इस व्यवस्था से छात्र दसवीं कक्षा तक अपनी पसंद की भाषा संयोजन को बनाए रख सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, नई जोड़ी गई तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। उसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक अंकों के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार सीबीएसई अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय लेते समय केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषा शिक्षा विद्यार्थियों के भविष्य के लिए वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार और अवसर प्राप्त करने में मदद करे। यदि अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का अध्ययन आवश्यक है, तो उसे सरल और प्रभावी ढंग से सिखाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दिशा में विज्ञान और गणित की पाठ्यपुस्तकों को द्विभाषी रूप में तैयार किया जा सकता है, जहाँ एक पृष्ठ पर अंग्रेजी और दूसरे पृष्ठ पर तेलुगु या अन्य मातृभाषा में सामग्री दी जाए। केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर डिजिटल वीडियो, चित्र और अन्य आधुनिक शिक्षण सामग्री भी विकसित की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के लिए सीखना अधिक सरल और प्रभावी बन सके।

भारत में त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा पहली बार 1968 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि छात्र विद्यालय स्तर पर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार–विमर्श किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प 1968 के माध्यम से इसे लागू किया गया।

उस समय हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (मुख्यतः दक्षिण भारतीय भाषा) तथा गैर–हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और विशेष रूप से तमिलनाडु में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद इस नीति में कई संशोधन किए गए। वर्तमान में तमिलनाडु में त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 1986 की शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख किया गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा है। सरकार का कहना है कि किसी भी भाषा को किसी पर थोपने का उद्देश्य नहीं है। इस नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता और बहुभाषिकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। फिर भी, भाषा नीति को लागू करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर, ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। यदि भाषा सीखना उनके विकास में सहायक बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यदि वह अतिरिक्त बोझ बन जाए, तो नीति निर्माताओं को उसके व्यावहारिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना होगा।

भारत और जापान को इंडो–पैसिफिक की नई परिकल्पना को आगे बढ़ाना चाहिए

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ''इंडो–पैसिफिक कमांड'' का नाम बदलकर फिर से ''पैसिफिक कमांड'' करने के निर्णय को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अमेरिका की घटती प्रतिबद्धता का संकेत मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे महज एक प्रशासनिक बदलाव बताकर खारिज कर रहे हैं। वास्तव में, दोनों ही दृष्टिकोण बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने में असफल हैं। इस निर्णय को अमेरिका की अपनी रणनीतिक और राष्ट्रीय पहचान की खोज के व्यापक संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' (ड।ळ।) आंदोलन ने लगातार अमेरिका को उस दौर से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का स्वर्णिम काल मानते हैंकृएक ऐसा समय जब अमेरिका सैन्य शक्ति, आर्थिक आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व के मामले में अद्वितीय था। ''डिपार्टमेंट ऑफ वॉर'' जैसे पुराने नामों को पुनर्जीवित करने तथा ऐतिहासिक सैन्य अड्डों के नाम बहाल करने के प्रस्ताव भी इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य दुनिया में अमेरिका की भूमिका की पुरानी अवधारणा को पुनर्स्थापित करना है। इस परियोजना से सहमत होना या न होना अलग बात है। महान शक्तियाँ समय–समय पर अपने भविष्य को आकार देने के लिए अपने इतिहास की ओर लौटती हैं। आज अमेरिका भी यही कर रहा है। ऐसे में भारत और जापान को अमेरिकी सैन्य कमान के नाम पर बहस में उलझने के बजाय एक अलग निष्कर्ष निकालना चाहिए। यदि वाशिंगटन अपनी रणनीतिक कथा को पुनर्परिभाषित कर रहा है, तो इंडो–पैसिफिक विचार के मूल शिल्पकारों को भी अपनी अवधारणा को पुनः सशक्त और प्रासंगिक बनाना चाहिए।

आधुनिक इंडो–पैसिफिक अवधारणा की उत्पत्ति वाशिंगटन में नहीं हुई थी। इसे सबसे प्रभावशाली रूप से जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रस्तुत किया था। उनके ''दो समुद्रों के संगम'' (ब्वदसिनमदबम वि जीम ज्ूव में) के विचार ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साझा रणनीतिक और सभ्यतागत क्षेत्र के रूप में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दृष्टि को अपनाया और समुद्री सहयोग से लेकर क्वाड (फनंक) जैसी पहलों के माध्यम से इसे व्यावहारिक रूप दिया।

हालाँकि, जैसे–जैसे इंडो–पैसिफिक अवधारणा को वैश्विक महत्व मिला, उसका अर्थ धीरे–धीरे सीमित होता गया। इसे मुख्य रूप से सैन्य गठबंधनों, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और चीन के उदय की चुनौती के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। निस्संदेह, ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे कभी भी इंडो–पैसिफिक की संपूर्ण परिभाषा नहीं थे। मूल दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरी थी।

इंडो–पैसिफिक केवल एक भू–राजनीतिक मंच नहीं है। यह दुनिया के सबसे पुराने परस्पर जुड़े सभ्यतागत क्षेत्रों में से एक है। दो हजार वर्षों से भी अधिक समय तक भारत, दक्षिण–पूर्व एशिया, चीन और जापान को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों ने केवल वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि विचारों, धर्मों, प्रौद्योगिकियों, कला परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों का भी आदान–प्रदान किया। बौद्ध धर्म भारत से पूरे एशिया में फैला। हिंदू सांस्कृतिक प्रभावों ने दक्षिण–पूर्व एशिया के अनेक राज्यों को आकार दिया। चीनी सभ्यता ने व्यापार, शिक्षा, नवाचार और समुद्री संपर्कों के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाया। इन सभी परस्पर संबंधों ने आधुनिक राष्ट्र–राज्यों के उदय से बहुत पहले एक स्थायी एशियाई समुदाय का निर्माण किया था।

यह साझा विरासत आज भी एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। इंडो–पैसिफिक की किसी भी सार्थक सभ्यतागत अवधारणा में चीन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्तमान रणनीतिक मतभेद वास्तविक हैं और कई मामलों में गंभीर भी हैं। उनका प्रबंधन स्पष्टता और यथार्थवाद के साथ किया जाना चाहिए। फिर भी, यह भी सत्य है कि चीन सदियों तक एशिया के ऐतिहासिक आदान–प्रदान का अभिन्न हिस्सा रहा है। इस विरासत को स्वीकार करने का अर्थ वर्तमान मतभेदों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि केवल प्रतिद्वंद्विता के आधार पर एक स्थायी क्षेत्रीय व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रह सकती है, लेकिन उसे इंडो–पैसिफिक का मुख्य आधार नहीं बनना चाहिए। आज अमेरिका और यूरोप दोनों अपनी सभ्यतागत पहचान को लेकर गहन विमर्श में लगे हुए हैं। इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय उद्देश्य और रणनीतिक दिशा जैसे प्रश्न घरेलू राजनीति और विदेश नीति दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। यह आत्ममंथन न तो असामान्य है और न ही अवांछनीय। महान शक्तियाँ समय–समय पर स्वयं को पुनर्परिभाषित करती हैं।

भारत और जापान को भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक विशिष्ट एशियाई दृष्टिकोण के साथ। उन्हें बहिष्कार पर आधारित नहीं, बल्कि जुड़ाव पर आधारित सभ्यतागत कथा का निर्माण करना चाहिए।

इंडो–पैसिफिक को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में समझा जाना चाहिए जो सदियों के संपर्कों से जुड़ा हुआ है और जो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए विविधता को समाहित करने में सक्षम है। ऐसा दृष्टिकोण दक्षिण–पूर्व एशिया को इंडो–पैसिफिक विमर्श के केंद्र में उसकी उचित जगह दिलाएगाकृएक ऐसी जगह जहाँ वह महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं, बल्कि हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच ऐतिहासिक सेतु के रूप में देखा जाए।

इसलिए, इंडो–पैसिफिक की नई परिकल्पना कई स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए। सुरक्षा सहयोग अनिवार्य रहेगा। आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाना होगा। तकनीकी सहयोग का महत्व लगातार बढ़ेगा। लेकिन इन सभी को शिक्षा, समुद्री विरासत, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, बौद्ध और ऐतिहासिक नेटवर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल संपर्क और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग से मजबूत किया जाना चाहिए। सभ्यता को रणनीति का स्थान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे समृद्ध करना चाहिए।

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की नई दिल्ली यात्रा इस चर्चा को आगे बढ़ाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है। रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग भले ही द्विपक्षीय एजेंडे में प्रमुख हों, लेकिन दोनों नेताओं को यह भी विचार करना चाहिए कि भारत और जापान मिलकर इंडो–पैसिफिक अवधारणा की उन व्यापक बौद्धिक और सभ्यतागत नींवों को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जिनके निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद फ्लोरिडा में होने वाला जी–20 शिखर सम्मेलन इस वैकल्पिक दृष्टि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है। भारत और जापान को अमेरिका से दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वाशिंगटन के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडो–पैसिफिक की परिभाषा केवल अमेरिकी रणनीतिक शब्दावली या विभिन्न अमेरिकी प्रशासन की बदलती प्राथमिकताओं तक सीमित न रह जाए।

अमेरिका अपने इतिहास और राजनीतिक विकल्पों के आधार पर दुनिया में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करता रहेगा। यह स्वाभाविक और अपरिहार्य है। भारत और जापान को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उनका लक्ष्य किसी पुराने युग को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि एक नए युग का निर्माण करना होना चाहिएकृएक ऐसा इंडो–पैसिफिक जो रणनीतिक रूप से सुरक्षित, आर्थिक रूप से गतिशील और सभ्यतागत रूप से आत्मविश्वासी हो। ''पैसिफिक कमांड'' पर चल रही बहस समय के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन इंडो–पैसिफिक विचार को नए सिरे से जीवंत बनाने का अवसर नहीं खोना चाहिए। यह अवधारणा एशिया में जन्मी थी और इसका अगला अध्याय भी एशिया में ही लिखा जाना चाहिए।

''भारत का मुक्त व्यापार समझौता अभियान''

पिछले पाँच वर्षों में भारत की व्यापार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चार ईएफटीए देशों, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद संपन्न हुआ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाल ही में हस्ताक्षरित नौ एफटीए अगले दस महीनों में पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जबकि तीन से चार अन्य समझौते अभी बातचीत के चरण में हैं।

वर्तमान में भारत के 15 एफटीए 27 देशों के साथ लागू हैं, जो उसके कुल व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद पहली बार भारत ने इतने व्यापक स्तर पर व्यापारिक एकीकरण देखा है और अब उसे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपने उत्पादों के लिए प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच उपलब्ध है।

भारत–यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता मई 2022 में लागू हुआ, जिसके तहत वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और औषधियों जैसे भारतीय उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप यूएई को भारत का माल निर्यात 2021–22 के 28.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 37.36 अरब डॉलर हो गया, जो 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

इसी प्रकार, भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जो दिसंबर 2022 में लागू हुआ, ने भारतीय निर्यातकों को 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क–मुक्त पहुंच प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 2021–22 के 4 अरब डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 7.3 अरब डॉलर हो गया, जो 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। वस्त्र, चमड़ा, मशीनरी और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्र, जिनमें भारत को तुलनात्मक निर्यात लाभ प्राप्त है, इस समझौते से विशेष रूप से लाभान्वित होने की संभावना रखते हैं।

यूरोपीय संघ के साथ हुआ एफटीए, अनुमोदन के बाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 27 यूरोपीय देशों के बाजारों तक भारतीय औषधियों, आईटी सेवाओं, वस्त्रों, रसायनों और कृषि–प्रसंस्कृत उत्पादों की प्राथमिकता प्राप्त पहुंच भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को दीर्घकाल में मजबूत करेगी।

व्यापार घाटाः व्यापक संदर्भ में

आलोचकों का तर्क है कि व्यापार समझौते अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं क्योंकि उन्होंने साझेदार देशों के साथ व्यापार घाटे को बढ़ाया है। हालांकि, आंकड़ों को अधिक सावधानी से समझने की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ औसतन 62 अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार घाटा दर्ज किया है। लेकिन इन आयातों का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पूंजीगत उपकरण और विशेष रसायनों जैसे औद्योगिक कच्चे माल का है, जो घरेलू विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं।

भारत का माल निर्यात 2021–22 के 314 अरब डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 441.7 अरब डॉलर हो गया, जो 40.6 प्रतिशत की वृद्धि है। वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 2025–26 में 860 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सरकार 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के माल निर्यात के विदेशी व्यापार नीति 2023 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें इन एफटीए की महत्वपूर्ण भूमिका है।

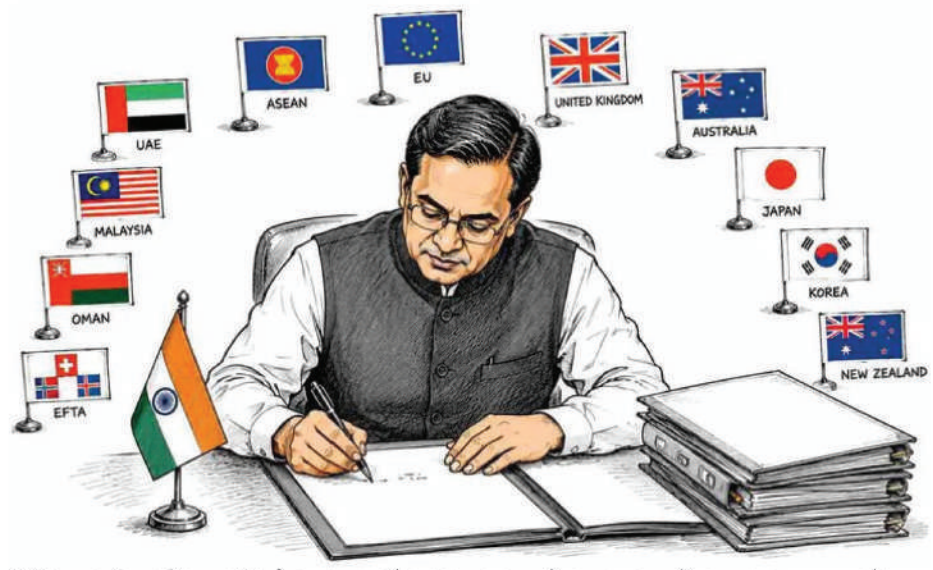

उपयोग और संरचनात्मक चुनौतियाँ

भारतीय निर्यातकों द्वारा एफटीए का उपयोग अभी भी अपनी पूरी क्षमता से कम है। इसे सुधारने के लिए ''ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफॉर्म'' की स्थापना की गई है, जिससे निर्यातकों को एफटीए के लाभों की जानकारी मिल सके। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तक पहुंच बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि छोटे निर्यातक भी इन व्यापारिक अवसरों का लाभ उठा सकें।

भारत को कई क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक होता है, जिससे देश में उत्पादन महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए, इस्पात और एल्युमीनियम जैसे कच्चे माल पर 7.5 से 10 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगता है, जबकि इन्हीं से बने मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और इंजीनियरिंग उत्पाद आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए एफटीए के तहत कम या शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

नीतिगत ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित होना चाहिए जहां कच्चे माल की आयात लागत तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक है।

सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को अंतिम विदाई देने तेहरान जाएंगी महबूबा मुफ्ती, ईरान ने भेजा था न्योता

जम्मू, 2 जुलाई (एजेंसियां)। अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार उनकी हत्या के 4 महीने बाद कराया जा रहा है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा शामिल होंगे। जबकि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ईरान से न्योता मिलने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आधिकारिक न्योता मिलने के बाद उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने ईरान जा रही हैं। पीडीपी प्रमुख मुफ्ती ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है,

यह न्योता (ईरान से) मिलना जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। मैं सुप्रीम लीडर को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाऊंगी।" इससे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान

के सुप्रीम लीडर के ऑफिस में अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के निदेशक मोहसिन कुम्मी की ओर से महबूबा मुफ्ती को भारत की एक खास मेहमान के तौर पर इस गंभीर अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक न्योता भेजा गया। महबूबा ने खामेनेई की हत्या के बाद खुलकर प्रदर्शन जताया था। न्योता पत्र में कहा गया कि ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की 28 फरवरी को हत्या कर दी गई थी, और राष्ट्रीय शोक की अवधि तथा इस्लामिक रिपब्लिक के प्रोटोकॉल के अनुसार, तेहरान में 3 से 6 जुलाई तक राजकीय अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। कुम्मी ने अपने न्योते में कहा, "ईरान और भारत को जोड़ने वाले गहरे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को देखते हुए, मैं भारत की एक खास मेहमान के तौर पर आपको इस गंभीर समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना बहुत सम्मान की बात मानता हूं।

महबूबा को लिखे पत्र में कहा गया, "आपकी मौजूदगी हमारी 2 महान प्राचीन सभ्यताओं के बीच गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का सबूत होगी।" कार्यक्रम के अनुसार, सुप्रीम लीडर खामेनेई को कल शुक्रवार (3 जुलाई) को तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला कॉम्प्लेक्स में अंतिम विदाई दी जाएगी, फिर अगले दिन श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। जबकि 6 जुलाई को अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा।

वहीं, भारत की ओर से खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्रों का कहना है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए निमंत्रण के बाद, दोनों भारत सरकार की ओर से 3 जुलाई से शुरू होने वाले अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। हालांकि पीएम मोदी के ईरान जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उनका व्यस्त कार्यक्रम है।

उन्हें विदेश यात्रा के लिए रवाना होना है। इस विदेश यात्रा में पीएम मोदी को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करना है। खामेनेई की मौत के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया था, कई दिन संघर्ष के बाद अमेरिका के साथ समझौता हुआ और युद्धविराम लागू हो गया। हालांकि जंग की वजह से राजकीय अंतिम संस्कार में देरी हुई। अब यह तेहरान के ग्रैंड मोसाला कॉम्प्लेक्स में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने के साथ शुरू होगा। 9 जुलाई को मशहद (खामेनेई का गृह नगर) में इमाम रजा दरगाह में दफनाने से पहले तेहरान और पवित्र शहर कोम में जुलूस निकाले जाएंगे।

अगले चुनाव माविगन बनाम अमरावती पर जनमत संग्रह होंगे: पूर्व सीएम जगनमोहन

विजयवाड़ा, 2 जुलाई (एजेंसियां)। वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के वैकल्पिक राजधानी के विज़न को दोहराया। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी अपने मुख्य चुनावी मुद्दे के तौर पर मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा-गुंटूर (माविगन) कॉरिडोर प्रस्ताव पर मजबूती से कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव 'माविगन बनाम अमरावती' पर सीधे जनमत संग्रह होंगे। जगन ने कहा, हम देखेंगे कि जनता हमें कितना समर्थन देती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तटीय कॉरिडोर मॉडल अमरावती प्रोजेक्ट का एक सही विकल्प है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरावती प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और बहुत ज़्यादा लागत शामिल है। उन्होंने कहा कि माविगन प्रस्ताव में प्राकृतिक फायदे और पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर पार्टी के चुनावी अभियान और घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।

हालांकि, पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने अपने पहले के तीन-राजधानी वाले प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की। जगन ने सीएम एन। चंद्रबाबू नायडू पर रियल एस्टेट घोटाला करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु और हैदराबाद में 5-स्टार निर्माण की लागत भी केवल 4,500 प्रति वर्ग फुट है: जगन उन्होंने भारी वित्तीय अंतर की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि जहां केंद्र सरकार ऑफिस की इमारतें 4,645 प्रति वर्ग फुट की लागत से बनाती है, वहीं राज्य सरकार 52 लाख वर्ग फुट के सचिवालय पर 20,439 प्रति वर्ग फुट की बहुत ज़्यादा लागत खर्च कर रही है।

जगन ने दावा किया, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे शहरों में, फाइव-स्टार निर्माण की लागत भी केवल 4,500 प्रति वर्ग फुट होती है। उन्होंने कहा कि अमरावती की अंदरूनी सड़कें 53 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से बनाई जा रही हैं, जबकि नेशनल हाईवे की मानक लागत 24 करोड़ प्रति किलोमीटर है।

गर्म चाय पीते ही छात्र की गई जान? डॉक्टर ने बता दिया असली सच

कोलकाता, 2 जुलाई (एजेंसियां)। चाय पीने से क्या किसी की जान जा सकती है? ऐसा सुनने में तो कभी आया नहीं। मगर, अब एक बुरी खबर है। दुर्भाग्य से कोलाकाता में 12वीं के एक छात्र दिप्तांशु महतो की थर्मस से सीधे खौलती गर्म चाय पीने से जान चली गई। मरने से पहले छात्र ने अपने पिता को बता दिया था कि उसने गर्म चाय क्यों पी? मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, चाय पीने से बच्चे की मौत का मामला कोलकाता के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम का है। यहां मंगलवार को खौलती चाय पीने से बारहवीं के एक छात्र की मौत हो गई। दिप्तांशु महतो के परिवार ने स्कूल अधिकारियों की घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक स्वामी इष्टेशानंद से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, जिन्होंने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छात्रों के साथ मारपीट और उत्पीड़न के आरोप में स्कूल के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

एनएसटीआर ने ब्रीडिंग सीज़न के दौरान कोर एरिया में टूरिज़्म पर रोक लगाई

ओंगोल, 2 जुलाई (एजेंसियां)। वन विभाग ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) की सालाना टाइगर ब्रीडिंग सीज़न की गाइडलाइंस के अनुसार, 2 जुलाई से 30 सितंबर तक नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (एनएसटीआर) के कोर एरिया में

इको-टूरिज़्म और इंसानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। एनएसटीआर प्रकाशम, कुरनूल और गुंटूर ज़िलों में कुल 3,727.82 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 2,444 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया और 1,283.82 वर्ग किलोमीटर बफ़र एरिया शामिल है।

पुराने प्रकाशम ज़िले में, मरकापुर और गिद्दलूर वन डिवीज़न टाइगर कंजर्वेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। मरकापुर डिवीज़न में इको-टूरिज़्म प्रोजेक्ट और कई मशहूर तीर्थ स्थल भी हैं, जहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। तीन महीने की पाबंदी के दौरान, रिज़र्व के कोर एरिया में सभी इको-टूरिज़्म गतिविधियाँ बंद रहेंगी। नल्लामाला जंगल में लगभग 300 तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण, सांभर और कई तरह के पक्षी शामिल हैं। यहाँ लगभग 70 तरह के स्तनधारी जीव, 30 तरह के सरीसृप और 100 तरह की तितलियाँ भी पाई जाती हैं। वन अधिकारियों ने बताया कि मॉनसून की शुरुआत कई प्रजातियों के लिए ब्रीडिंग सीज़न की शुरुआत होती है, जबकि बारिश से घास उगती है और जंगल की हरियाली बढ़ती है। पेद्दा डोरनाला फ़ॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर हरि और नेक्कंती फ़ॉरेस्ट रेंज इंचार्ज ऑफ़िसर साई कुमार ने कहा, 2 जुलाई से 30 सितंबर तक का यह तीन महीने का समय मॉनसून की शुरुआत का होता है और बाघों की ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है।

पति के खर्राटों से परेशान पत्नी ने मांगा तलाक:बोली- वे बहुत अच्छे हैं, पर रातभर जाग नहीं सकती

भोपाल, 2 जुलाई (एजेंसियां)। दिन में पति-पत्नी का रिश्ता सामान्य था, लेकिन रात होते ही पति के तेज खर्राटे दोनों के बीच तनाव की वजह बन जाते थे। लगातार नींद पूरी न होने से परेशान पत्नी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। फैमिली काउंसलर से उसने कहा, वे बहुत अच्छे हैं, पर मैं रातभर जाग नहीं सकती। डॉक्टरों के अनुसार, मोटापा और बदलती जीवनशैली के कारण खर्राटों और स्लीप एपनिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं।

यह समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिवारिक और दांपत्य जीवन पर भी असर डाल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज खर्राटों को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में सोते समय शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 95 प्रतिशत से घटकर 50–60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

'ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण शरण सिंह को भी खतरा'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का सवाल

नई दिल्ली, 2 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज से लोकसभा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हुए बड़ा सवाल किया है। केजरीवाल ने सिंह का जिक्र उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में किया। उन्होंने कहा कि इनके एक बड़े नेता हैं बृजभूषण।

उनका कहना है कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़े बड़े नाम आएंगे और मुझे खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिनका नाम बृजभूषण को भी खतरा है। बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि बड़े नाम शामिल हैं, नाम लिया तो मुझ पर आंच आ सकती है।

ताकतवर लोग भी नाम लेने से डर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह घोटाले के दस्तावेज लेकर एसआईटी के पास गए तो जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था। एसआईटी ने कहा कि ज़मीन के घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं। आप नेता ने कहा कि चंदा चोरों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी तो चंपत राय को ही बचाया जा रहा है लेकिन बात उससे बहुत ऊपर की है। आप नेता ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सारे प्यादे हैं। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए गठित विशेष जांच समिति पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए कौन सी एसआईटी बनती है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 में जब अयोध्या में जमीनों से जुड़ी अनियमितिताएं सामने आईं थीं तब भी एक एसआईटी बनाई गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। मामला एसआईटी बनाकर रफा दफा कर दिया गया।

मुंबई में भारी बारिश, समुद्र से दूर रहने की चेतावनी

15 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं; मानसून की राजस्थान में 7 दिन की देरी से एंट्री

भोपाल/जयपुर/लखनऊ, 2 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद चार जिलों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 172एमएम बारिश हुई। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने गुरुवार दोपहर समुद्र में करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी है। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। मानसून ने गुरुवार को 7 दिन की देरी से राजस्थान और 5 दिन की देरी से दिल्ली में एंट्री ली। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। राजस्थान के जयपुर-दौसा समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इधर, मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। इंदौर में बारिश में कार नाले में गिर गई। सीहोर में बारिश के तेज बहाव में बाइक भी बह गईं। खराब मौसम के चलते उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार

सीएम अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल

जम्मू, 2 जुलाई (एजेंसियां)। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पार्टी पर कहा कि यह जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के आस-पास होगा। उन्होंने मीडिया में यह घोषणा की और कहा कि कैबिनेट का विस्तार उनकी जिम्मेदारी है और यह जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के आस-पास, यानी उससे पहले या बाद में होगा। उमर अब्दुल्ला सरकार तीन और मंत्रियों को शामिल कर सकती

है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नौ मंत्रियों तक की अनुमति है, जबकि अभी मंत्रिपरिषद की संख्या छह है। इस घोषणा के बाद उन लोगों के बारे में अफवाहों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिन्हें हटाया जा सकता है

और जिन्हें उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में मौका मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में निश्चित रूप से तीन नए चेहरे शामिल होंगे, लेकिन कैबिनेट के कुछ मौजूदा मंत्रियों के अहम विभाग छिन सकते हैं, और विस्तार के बाद, जब मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा और फेरबदल करेंगे, तो कम से कम दो मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन मॉनसून सत्र के पहले दिन होगा, जिसके 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर पार्टी के भीतर के दबाव की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, '3 जून को हुई दाचीगाम बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी हो गया है।' बैठक में, सत्ताधारी एनसी के विधायकों और पार्टी का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय सदस्यों ने फंड के बंटवारे और व्यवहार को लेकर मंत्रियों, खासकर डिप्टी सीएम की कड़ी आलोचना की।

'तमिलनाडु में टीवीके के विधायक तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ का खेल शुरू'

संजय राउत का बड़ा आरोप

मुंबई, 2 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी के एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता ही कि एक दिन अमित शाह और पीएम मोदी एक साथ बैठकर बोलेंगे की मैं तुझे फोड़ता हूं तु मुझे फोड़, पार्टी तोड़ने के बाकी कोई बचेगा नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, दोनों ही एक दूसरे को फोड़ेंगे। बीजेपी को ही फोड़ देंगे। लोगों में पार्टी फोड़ने का इतना नशा है कि अगर कुछ नहीं बचा तो अपनी पार्टी ही फोड़ देंगे। संजय राउत ने आगे आरोप लगाया कि तमिलनाडु में टीवीके के विधायक तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ का खेल हो गया।

15 विधायक तोड़कर टीवीके सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा, इन लोगों को चैन नहीं है। इन्हें नींद नहीं आती। अगर किसी को एक दिन नहीं तोड़ा तो इन लोगों को नींद नहीं आती। उन्होंने आगे कहा, क्या कर सकते हैं देश का लोकतंत्र इतने नीचे स्तर पर गिर चुका है। आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र था। उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष क्या करेगा। सेंट्रल एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल कर विपक्ष की पार्टियां तोड़ रहे हैं। जिस दिन यह लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और सुरक्षा एजेंसियां हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 मिनट में 10 टुकड़े हो जाएंगे। एक भी पार्टी नहीं बचेगी। न एकनाथ शिंदे, अजीत पवार गुट और न बीजेपी बचेगी।

सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी, सीबीआई हमें दे दो। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने केंद्र और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई की गई है, जबकि इस मामले में लिप्त गंभीर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा, सबसे पहले चंपत राय को गिरफ्तार कीजिए। अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कीजिए। गोपाल राय को गिरफ्तार कीजिए।

कांग्रेस में नहीं होगा एनसीपी-एसपी का विलय

शरद पवार ने कर दिया साफ

मुंबई, 2 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी-एसपी की कांग्रेस में विलय की अटकलों पर शरद पवार ने ब्रेक लगा दिया है। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के दावे को खारिज कर दिया है। शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ना ही हमारी पार्टी में कोई टूट होने जा रही है और ना ही पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया था कि शरद पवार के गुट वाली एनसीपी का जल्द ही उनकी पार्टी में विलय होगा। कांग्रेस नेता ने कहा था कि इसके लिए दिल्ली में हाईकमान के साथ नेताओं की बैठक चल रही है।

हालांकि, अब शरद पवार ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल, महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई दिनों से ये चर्चा जारी थी कि क्या शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं? आपको बता दें कि शरद पवार ने साल 1999 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और एक अलग पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की स्थापना की थी। हालांकि, साल 2023 में एनसीपी में टूट हो गई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत की और एनसीपी उनके हाथों में चली गई। इसके बाद शरद पवार ने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की स्थापना की थी। अजित पवार की एनसीपी भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति का हिस्सा बनी और शरद पवार की एनसीपी ने विपक्षी खेमे महाविकास अघाड़ी का साथ दिया।

कल्याण में एक ही स्कूल की 4 नाबालिग छात्राएं लापता राज्यभर में पुलिस कर रही तलाश; सर्च ऑपरेशन जारी

मुंबई, 2 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र के कल्याण शहर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही स्कूल में पढ़ने वाली चार नाबालिग छात्राएं रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। घटना बाजारपेठ पुलिस थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित उर्दू हाईस्कूल में पढ़ने वाली चारों छात्राएं 29 जून को रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं। हालांकि, शाम तक वह अपने घर वापस नहीं लौटीं।

परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने बाजारपेठ पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस स्कूल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा छात्राओं की मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

ग्रेट निकोबार परियोजना: कांग्रेस ने पीएम मोदी को याद दिलाईं पांच याचिकाएं

क्या तबाही की ओर बढ़ रहे हम?

नई दिल्ली, 2 जुलाई (एजेंसियां)। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को विवादास्पद ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस परियोजना के खिलाफ अपने वर्षों के विरोध को दर्ज किया है, जिसे उन्होंने पर्यावरणीय आपदा की ओर एक कदम करार दिया है।

एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर अपनी व्यापक सार्वजनिक भागीदारी का एक संकलित संग्रह सार्वजनिक किया, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट, संसदीय हस्तक्षेप और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ आधिकारिक पत्राचार के साथ-साथ उनकी प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना और उस अद्वितीय जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके विनाशकारी प्रभावों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में मेरे व्यापक सार्वजनिक जुड़ाव को जानने में रुचि रही है।

यहां अधिकांश सोशल मीडिया पोस्ट, संसद में दिए गए कुछ संक्षिप्त भाषण और सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों को लिखे गए पत्र और उनके जवाबों का संकलन पेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यह विशाल विकास परियोजना द्वीप के प्राचीन, जैव

विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक विनाशकारी खतरा पैदा करती है। रमेश ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्रेट निकोबार में पर्यावरणीय आपदा की ओर अपना कदम बढ़ाते रहेंगे, इसलिए इस तरह के और भी सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे।' उन्होंने जनहितैषी और जागरूक नागरिकों और नागरिक समाज समूहों द्वारा दायर की गई पांच अलग-अलग याचिकाओं पर भी प्रकाश डाला, जिनकी सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में हो रही है।

ये चुनौतियां इस प्रकार हैं।

कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के उल्लंघन पर आधारित चुनौती।

गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के उल्लंघन पर आधारित चुनौती।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 और इसके नियम, 2008 के उल्लंघन पर आधारित चुनौती।

तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना, 2019 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन पर आधारित चुनौती।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 16 फरवरी, 2026 के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती। देश की पारिस्थितिक चेतना की परीक्षा हो रही है।

इस बीच, सरकार के अनुसार, यह परियोजना पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्ग से द्वीप की निकटता (लगभग 40 समुद्री मील की दूरी) का लाभ उठाने और रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करने का प्रयास करती है।

क्या कृति सेनन का कबीर बहिया से हो गया ब्रेकअप?

एक तस्वीर से एक्ट्रेस ने कर दी अफवाहें फैलाने वालों की बोलती बंद

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म 'कॉकटेल' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनका अंदाज और ड्रेसिंग स्टाइल काफी पसंद किया, लेकिन अब एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में चर्चाएं शुरू हुई थीं कि एक्ट्रेस का ब्रेकअप हो गया है। बिजनेसमैन कबीर बहिया संग उनके रिश्ते को लेकर पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कबीर की एक दूसरी महिला के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद दोनों के ब्रेकअप की अफवाहें उड़ने लगी थीं। हालांकि कृति ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कबीर के साथ एक बेहद करीबी और रोमांटिक तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस चर्चित रिश्ते पर पहली बार खुलकर बात भी की। एक्ट्रेस ने साफ कर दिया कि अफवाहें उड़ाने वाले सिर्फ कयास लगाते रहेंगे, लेकिन इससे उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।

'हाफ इयरली डंप' में दिखी कबीर संग नजदीकी

कृति सैनन ने इंस्टाग्राम पर पिछले छह महीनों की अपनी कुछ अनदेखी यादों का एक हाफ इयरली डंप शेयर किया। इस पोस्ट में उनकी जिंदगी के कई खूबसूरत पल कैद थे, जैसे उनकी पेट डॉग के साथ यात्राएं, 'कॉकटेल 2' की सह-कलाकार रश्मिका मंदाना के साथ गले मिलने की तस्वीर और बहन नुपुर सैनन के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना। इन सबमें जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, उसमें कृति और कबीर बहिया एक लाइव परफॉर्मेंस का आनंद लेते हुए एक-दूसरे को बाहों में थामे नजर आ रहे हैं। जहां कबीर आइवरी कढ़ाईदार शेरवानी में सजे हैं, वहीं कृति ने काले रंग की हुडी पहनी हुई है, जिस पर लिखा है कि इमोशनली इनवेस्टेड, फाइनेंशियली ब्रोक। कृति ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'हाफ इयरली डंप! कुछ पल जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं आ सके.. और कुछ कभी आएंगे भी नहीं..।'

कबीर बहिया की किसी दूसरी महिला के साथ फोटो सामने आई थी, जिसके बाद इंटरनेट पर यह चर्चा शुरू हो गई कि कृति और कबीर का ब्रेकअप हो गया है। मगर कृति ने अपनी ताजा पोस्ट से इन दावों पर पानी फेर दिया। इस बीच कबीर के करीबी एक सूत्र ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया कि वायरल तस्वीर को पूरी तरह से गलत समझा गया है। सूत्र के मुताबिक, 'इंटरनेट पर कबीर के साथ दिख रही लड़की उनकी पारिवारिक मित्र है, जिसे वह अपनी बहन की तरह मानते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग कितनी जल्दी बिना सोचे-समझे किसी भी बात पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं और झूठी कहानियां फैलाने लगते हैं।'

कबीर संग रिश्ते पर क्या बोलीं कृति?

एक इंटरव्यू के दौरान कृति से उनके कथित रिलेशनशिप और बहन नुपुर सैनन की गायक स्टेबिन बेन के साथ हुई शादी में कबीर की मौजूदगी को लेकर सवाल किया गया। कृति ने अपनी पर्सनल लाइफ पर कोई भी सीधा जवाब न देते हुए साफ किया कि वह अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना पसंद करती हैं। अभिनेत्री ने कहा, 'जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगी। जिस दिन मेरी शादी होगी, मैं खुद इस पर बात करूंगी। कुछ चीजें सिर्फ मेरे, मेरे करीबी लोगों और हमारे बीच के लिए ही होती हैं।' जब इंटरव्यूअर ने शादी में नजर आए उस खास दोस्त का दोबारा जिक्र किया तो कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं किसी भी बात को न तो स्वीकार करूंगी और न ही इससे इनकार करूंगी।'

बॉक्स ऑफिस पर 'कॉकटेल 2' का धमाल

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति सैनन की हालिया रिलीज फिल्म 'कॉकटेल 2' इस समय सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने अब तक भारत में 103.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 86.80 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2026 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में कृति के साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

'मैं उर्फी जावेद हूं, रीता भारद्वाज नहीं'

मुस्लिम से हिंदू ब्राह्मण बनने पर टीवी एक्ट्रेस का दो टूक जवाब- सारी अफवाहें बकवास!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन दावों पर अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद ने प्रतिक्रिया दी है, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नाम बदलकर 'रीता भारद्वाज' रख लिया है.

उर्फी जावेद ने क्या सच में धर्म परिवर्तन किया है?

टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह के दावे वायरल हो रहे थे जिसमें कहा गया कि उर्फी ने इस्लाम धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है. अब उनका नया नाम 'रीता भारद्वाज' है. इस तरह की खबरें फैलने के बाद अब खुद उर्फी ने सामने आकर इन अफवाहों का खंडन किया है.

'ये पूरी तरह फर्जी खबर है'

उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए साफ किया कि उन्होंने न तो अपना धर्म बदला है और न ही अपना नाम. उन्होंने वायरल पोस्ट्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि यह पूरी तरह फर्जी खबर है और लोग बिना किसी सच्चाई के ऐसी बातें फैला रहे हैं. उर्फी ने लोगों से अपील की कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें.

सोशल मीडिया पर तेजी से फैली थी अफवाह

दरअसल, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे पोस्ट वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि उर्फी ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम रीता भारद्वाज रख लिया है. हालांकि इन दावों को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आए. बाद में एक्ट्रेस के इस बयान ने इन अफवाहों के निराधार साबित कर दिया.

उर्फी जावेद अपने अनोखे फैशन सेंस और बेबाक बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है और उनसे जुड़ी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं. हालांकि, कई बार उनके नाम पर फर्जी दावे और एडिटेड पोस्ट्स भी वायरल होते रहते हैं, जिनका उन्हें खुद सामने आकर जवाब देना पड़ता है. उर्फी के बयान के बाद कई फैंस ने उनका समर्थन किया और फर्जी खबरें फैलाने वालों की आलोचना की. वहीं कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के वायरल होने वाली खबरों पर चिंता भी जताई।

मशहूर थिएटर और फिल्म निर्देशक विजया मेहता का निधन

पीएम मोदी बोले- सिनेमा की महान हस्तियों में हमेशा याद की जाएंगी

भारतीय रंगमंच और सिनेमा की दिग्गज हस्ती विजया मेहता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि विजया मेहता भारतीय संस्कृति और सिनेमा की सबसे महान हस्तियों में हमेशा याद की जाएंगी। आधुनिक मराठी रंगमंच की अग्रणी हस्ती के रूप में विजया मेहता अपनी रचनात्मकता और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थीं। उनके काम ने कई पीढ़ियों के कलाकारों, निर्देशकों और रंगमंच प्रेमियों को प्रेरित किया। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, प्रशंसकों और पूरे कला जगत के साथ हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि विजया मेहता ने अपने नाटकों और फिल्मों के माध्यम से मराठी रंगमंच और सिनेमा को अमूल्य योगदान दिया। उनके नाटकों ने मराठी थिएटर में एक नई क्रांति लाई और अनेक महान कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। उनका निधन मराठी रंगमंच और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

फडणवीस ने जताया शोक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि विजया मेहता के निधन की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने अभिनय से अपनी पहचान बनाई और बाद में कई यादगार नाटकों का निर्देशन किया।

उन्होंने अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मियों को तैयार किया और फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार भी हमेशा याद किए जाएंगे। उनके निधन के साथ एक पूरा कलात्मक दौर इतिहास के पर्दे के पीछे चला गया। वहीं, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि विजया मेहता को दी श्रद्धांजलि।

कोर्ट पहुंचा 'काला हिरण' का विवाद

सलमान खान की याचिका पर टली सुनवाई

सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण' के बीच जारी विवाद अब कोर्ट तक खिंच गया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है। जानिए केस को लेकर क्या है नया अपडेट।

मेकर्स ने दिया आश्वासन

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सोमवार तक न तो फिल्म रिलीज की जाएगी और न ही इसका ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे तब तक फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन के लिए भी नहीं भेजेंगे। मेकर्स के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक फिल्म का सिर्फ टीजर रिलीज हुआ है और फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान की याचिका पर वे जल्द ही अपना पूरा जवाब दाखिल करेंगे।

सोमवार को होगी अगली सुनवाई

जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि अगर मेकर्स को पूरा भरोसा है कि फिल्म अभी रिलीज नहीं होगी, तो उन्हें इसे आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। इसके बाद मेकर्स ने साफ तौर पर कोर्ट को आश्वासन दिया कि सोमवार तक फिल्म को CBFC के पास नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया और अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय कर दी।

सलमान के वकील का बयान

इससे पहले सलमान खान के वकील ने दलील दी थी कि मेकर्स को साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि फिल्म रिलीज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह मामला सलमान खान के 'पर्सनैलिटी राइट्स' के उल्लंघन से जुड़ा है और इसके लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है। फिलहाल कोर्ट ने मेकर्स के आश्वासन को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जहां विवाद से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।

सच में रिलीज होते ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' कमाने लगी मुनाफा

'वेलकम टू द जंगल' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं। फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है, यही वजह है कि एक हफ्ते के भीतर ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब सवाल आता है कि फिल्म का असल बजट क्या है, क्या फिल्म मुनाफा कमा रही है, जानने के लिए नीचे स्क्रोल करें।

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और दिशा पाटनी जैसे 30 से अधिक दिग्गज कलाकारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। फिल्म को लेकर बाजार में कई तरह की अफवाहें थीं, जिनमें सबसे बड़ी चर्चा इसके भारी-भरकम बजट को लेकर थी। कयास लगाए जा रहे थे कि इस मल्टीस्टारर फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपये के आसपास है। IMDb पर भी 200-300 करोड़ के बीच बजट दर्ज किया गया, लेकिन अब फिल्म के निर्देशक अहमद खान ने खुद सामने आकर इस बजट का असली सच उजागर कर दिया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ किया कि फिल्म का बजट किए जा रहे दावों के आधे से भी कम है।

300 करोड़ नहीं, महज इतने बजट में बनी फिल्म

निर्देशक अहमद खान ने टाइम्स नाओ के दिए एक हालिया इंटरव्यू में बजट की तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए बताया कि फिल्म का बजट उतना बड़ा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। अहमद खान के मुताबिक, 'पूरी स्टारकास्ट, एक्शन सीक्वेंस, गानों और यहां तक कि ब्याज के पैसों को भी जोड़ लिया जाए तो 'वेलकम टू द जंगल' का कुल बजट 115 करोड़ से 125 करोड़ के बीच ही रहा है।' फिल्म की मेकिंग को लेकर उन्होंने एक और दिलचस्प खुलासा किया। अहमद ने बताया कि इस पूरी फिल्म की शूटिंग महज 75 शिफ्ट्स में पूरी कर ली गई थी। हर शिफ्ट सिर्फ 8 घंटे की होती थी, जिसमें से

लंच और अन्य ब्रेक हटाकर वे रोजाना केवल 6 से 6.5 घंटे ही शूटिंग करते थे। इतने कम समय में इतनी बड़ी फिल्म को समेटना वाकई तारीफ के काबिल है।

अक्षय कुमार की इस खास डील ने बचाए करोड़ों रुपये

इस फिल्म के बजट को इतना नियंत्रित रखने के पीछे सबसे बड़ा हाथ खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का है। अमूमन फिल्मों के लिए भारी-भरकम फीस लेने वाले अक्षय ने इस फिल्म के लिए अपनी रणनीति बदल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए शुरुआत में एक भी रुपया फीस नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने मेकर्स के साथ प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल पर काम किया। वहीं फिल्म की रिलीज से पहले हुए इवेंट में अक्षय कुमार से सवाल किया गया था कि क्या उन्होंने 1.7 करोड़ रुपये इस फिल्म के लिए फीस ली है, जिसके जवाब ने अक्षय कुमार ने साफ कहा कि उनकी कमाई इससे भी कम थी। उन्होंने फिल्म के लिए बहुत कम पैसे लिए हैं। अक्षय ने कहा, 'जो आपने कहा मैंने उतना भी नहीं है, मैंने बहुत कम चार्ज किया है। इस फिल्म की कहानी नीरज वोहरा ने लिखी है, मैंने नीरज वोहरा, प्रियदर्शन और नीरज वोहरा से बहुत कुछ सीखा है, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब थी। नीरज से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये कहानी उसकी ही थी, साथ में फिरजो नाडियडवाला है, जिसे मैं 36 सालों से जानता हूं, मैं उसके पास स्ट्रगलिंग करता था।'

क्या रहा प्रोडक्शन का कुल खर्चा?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय के इस कदम से फिल्म की शुरुआती लागत बहुत कम हो गई। अगर फिल्म के बजट के बंटवारे को समझें तो शूटिंग और प्रोडक्शन लागत लगभग 60 करोड़ रही। बाकी स्टारकास्ट की फीस 35 करोड़ में निपट गई। निर्देशक और टेक्निकल टीम का खर्च सिर्फ 15 करोड़ के आसपास रहा। प्रिंट और पब्लिसिटी, यानी प्रमोशन का खर्च 15 करोड़ बताया गया। इस तरह पूरी फिल्म का गणित 125 करोड़ पर आकर रुक गया। अक्षय अब फिल्म की पूरी लागत वसूल होने के बाद होने वाले शुद्ध मुनाफे में से अपना हिस्सा लेंगे।

रिलीज होते ही कैसे मुनाफे में आ गई फिल्म?

ट्रेड ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर दुनिया भर में 120 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और यह तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिल्म के मुनाफे की कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। अहमद खान ने खुलासा किया कि फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को करीब 120 करोड़ में बेच दिया गया था। इसका सीधा मतलब यह है कि मेकर्स अपनी लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलीज से पहले ही सुरक्षित कर चुके थे। अब बॉक्स ऑफिस से होने वाली हर कमाई सीधे मेकर्स की जेब में जा रही है और फिल्म पूरी तरह से मुनाफे के ट्रैक पर दौड़ रही है।

'अल्फा' की रिलीज से पहले आलिया भट्ट ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, सेलेब्स ने किए कमेंट

आलिया भट्ट की अदाकारी वाली फिल्म 'अल्फा' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो फैंस का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में आलिया भट्ट फैंस को उस ट्रेनिंग की झलक दिखा रही हैं जिसने उन्हें अपने करियर के सबसे मुश्किल रोल में ढलने में मदद की। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपने जबरदस्त मॉर्निंग वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने काले रंग का ड्रेस पहना है। इस पर अल्फा लिखा है। आलिया भट्ट कई तरह के वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा 'अल्फा के दौरान सुबह का रूटीन। जोश और गुस्से के साथ।'

आलिया भट्ट का वर्क आउट फैंस को बहुत पसंद आया है। उन्होंने आलिया भट्ट की काफी तारीफ की है। अभिनेत्री नेहा मलिक ने लिखा 'फेवरेट'। विनीत कुमार सिंह ने कमेंट बॉक्स में दिल और फायर वाला इमोजी बनाया है। एक और यूजर ने लिखा 'अल्फा को रिलीज होने में 2 दिन बचे हैं।' एक और यूजर ने लिखा 'वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर' हैं।

ख्याल रहे कि फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया के अलावा शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम किरदारों में हैं। 'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है।

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com